

Daily Current Affairs

Date : 09 June, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान में 'पीएमश्री योजना' का क्रियान्वयन
2.	डेडिकेटेड इंटरवेंशन एंड लाइफ सेविंग स्टेमी इमरजेंसी (DILSE) का पायलट प्रोजेक्ट
3.	राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विकसित 'शाला दर्पण पोर्टल'
4.	HZL का इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट : चंदेरिया (चित्तौड़गढ़)
5.	राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में खजूर की खेती
6.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी को वीर चक्र 2. 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता 3. युवा संगम का छठा चरण 4. प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा 5. नॉर्थ जोन नेशनल स्ववैश हाई-परफॉर्मेंस कैम्प : जयपुर 6. देवांशी शर्मा : विश्व योगासन चैंपियनशिप - 2026 में स्वर्ण पदक 7. MGSU एवं RKCL के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) 8. इंडिया फूड बिजनेस एक्सपो - 2026 9. राजस्थान लीग सीनियर विमेंस A डिवीज़न 2025-26 10. 'फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026' में राजस्थान के 2 युवा शामिल
7.	फूड प्लैनेट पुरस्कार 2026
8.	नॉर्वे शतरंज, 2026
9.	मुक्केबाज जैस्मीन लैंबोरिया
10.	एस भरत
11.	व्यापार करने में सुगमता: भारत के व्यापार ढांचे को सुदृढ़ बनाना
12.	रक्षा अलंकरण समारोह, 2025 (चरण-I)
13.	प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान: 10 वर्ष पूर्ण
14.	भव्य योजना एवं पोर्टल

-:1:-



UTKARSH CLASSES |



support@utkarsh.com |



: 9829 213 213

Daily Current Affairs

 Date : 09 June, 2026



15.	नेपाल के 'नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस (NPI)' के साथ UPI को जोड़ा गया
16.	केशम द्वीप
17.	भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक



--:2::--



UTKARSH CLASSES |  support@utkarsh.com |  : 9829 213 213



राजस्थान परिदृश्य



राजस्थान में 'पीएमश्री योजना' का क्रियान्वयन



चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड (PAB) बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु राजस्थान के सभी पीएमश्री विद्यालयों के लिए ₹226.38 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।

--3--

मुख्य बिन्दु:

- राजस्थान के पीएमश्री विद्यालयों के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है।
- राज्य में संचालित पीएमश्री स्कूल 'उत्कृष्ट प्रबंधन' की अवधारणा पर आधारित हैं, जहाँ विद्यार्थियों को व्यावहारिक वातावरण एवं आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- राजस्थान के विद्यालयों में 'पीएमश्री योजना' का 2 चरणों में संचालन किया जा रहा है।
- **प्रथम चरण** : राज्य के 402 विद्यालयों का चयन किया गया।
- **द्वितीय चरण** : राज्य के 33 जिलों से 237 विद्यालयों का चयन किया गया।
- इस योजना के तहत राज्य में चयनित कुल 639 विद्यालयों में 16 प्राथमिक, 123 उच्च प्राथमिक, 18 माध्यमिक और 482 उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं।
- प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PMSHRI) योजना के तहत राजस्थान में विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिनमें से प्रदेश के 500 पीएमश्री विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी और 142 विद्यालयों में ओ-लैब स्थापित की गई हैं।
- **संबंधित विभाग** : राष्ट्रीय स्तर पर 'स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग' तथा राज्य में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् और शिक्षा विभाग।

प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री)

- **मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन** : 7 सितंबर, 2022
- **प्रकार** : केंद्र प्रायोजित योजना।
- **उद्देश्य** : 14,500 मॉडल स्कूलों की स्थापना करना।
- चयनित विद्यालयों में समग्र शिक्षा, 21वीं सदी के अनुकूल कौशल विकास तथा पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।

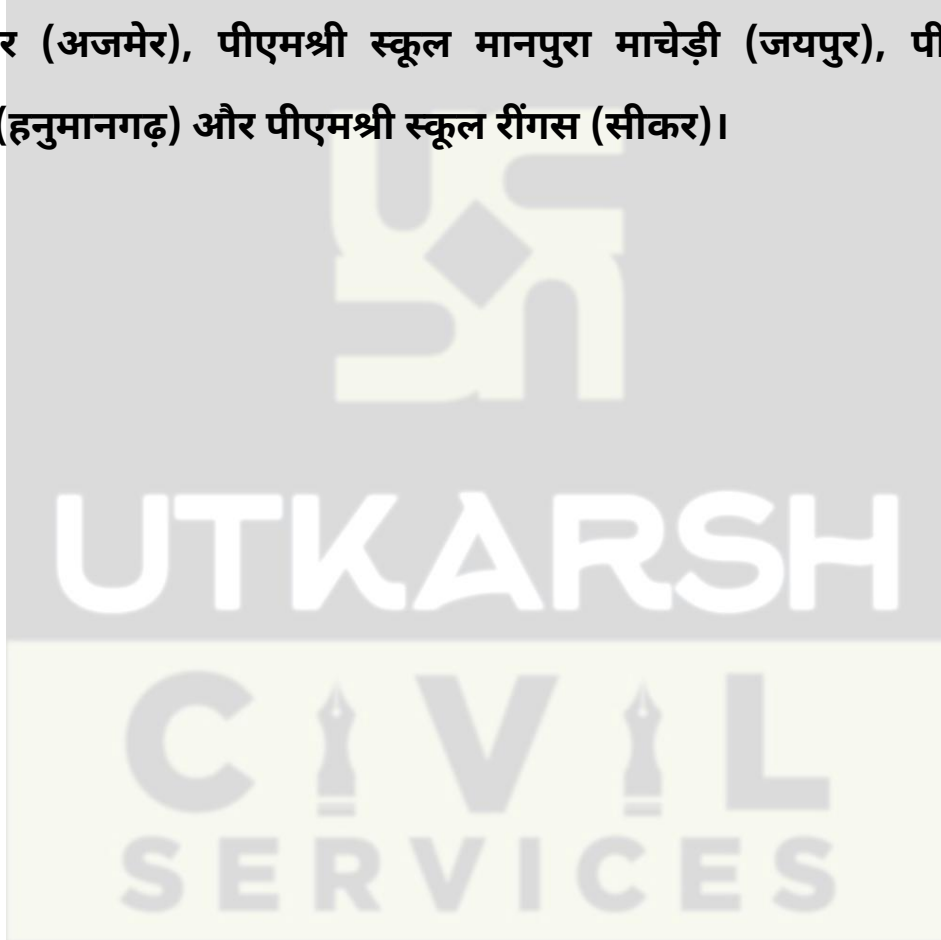
Daily Current Affairs

 Date : 09 June, 2026



फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सभी 639 पीएमश्री विद्यालयों की पहली बार राज्य स्तरीय रैंकिंग जारी की गई।
- रैंकिंग के अनुसार शीर्ष पाँच पीएमश्री विद्यालय : पीएमश्री स्कूल धवा (जोधपुर), पीएमश्री स्कूल सावर (अजमेर), पीएमश्री स्कूल मानपुरा माचेड़ी (जयपुर), पीएमश्री स्कूल जोधकिया (हनुमानगढ़) और पीएमश्री स्कूल रींगस (सीकर)।



-:5:-



UTKARSH CLASSES |  support@utkarsh.com |  : 9829 213 213

डेडिकेटेड इंटरवेंशन एंड लाइफ सेविंग स्टेमी इमरजेंसी (DILSE) का पायलट प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों?

- हार्ट अटैक के मरीजों को गोल्डन आवर (शुरुआती 1 घंटा) में इलाज उपलब्ध करवाने के लिए अजमेर एवं कोटा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और बड़े अस्पतालों में डेडिकेटेड इंटरवेंशन एंड लाइफ सेविंग स्टेमी इमरजेंसी (DILSE) योजना का पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया है।

Pilot Project of the

DEDICATED INTERVENTION AND LIFE-SAVING STEMI EMERGENCY (DILSE)

in Rajasthan

Timely Intervention. Proven Care. Saving Lives.



Saving Lives
Rapid treatment for STEMI patients through timely intervention.



Dedicated Care
Dedicated Cath Labs and trained teams for round-the-clock STEMI care.



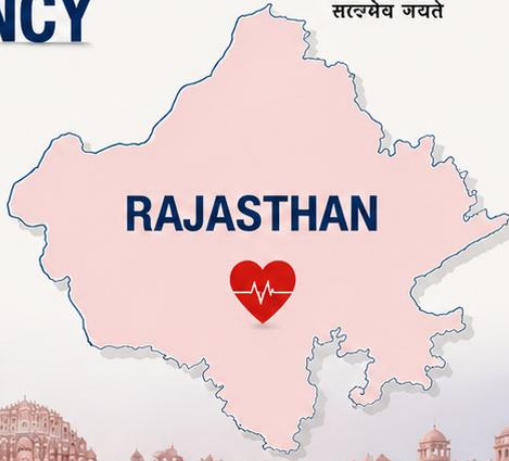
Faster Response
Streamlined referral and transport system to reduce door-to-balloon time.



Stronger Network
Creating a robust STEMI care network across Rajasthan hospitals.

Government of Rajasthan
सरकार महाराष्ट्र

RAJASTHAN



मुख्य बिन्दु:

- इसके तहत चयनित CHCs पर दिल के मरीज को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ (ECG) जांच और दवाओं के जरिए इलाज दिया जाएगा तथा थ्रोम्बोलाइसिस विधि से इलाज होगा।

Daily Current Affairs

 Date : 09 June, 2026



- थ्रोम्बोलिसिस (Thrombolysis) एक आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसका उपयोग नसों में जमे हुए खतरनाक खून के थक्कों (Blood Clots) को घोलकर रक्त प्रवाह को सामान्य करने के लिए किया जाता है। इसे थ्रोम्बोलिटिक या फाइब्रिनोलिटिक थेरेपी भी कहा जाता है।
- अजमेर के 23 और कोटा के 19 अस्पताल इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हैं। पायलट प्रोजेक्ट के बाद योजना प्रदेशभर में लागू की जाएगी।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

मिशन ओबी लॉस (Mission OB Loss):

- ओबेसिटी के खतरे को रोकने और मोटापे से जुड़ी बीमारियों; जैसे - उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, फैटी लीवर, घुटने का दर्द, मधुमेह और कैंसर को रोकने के लिए चिकित्सा विभाग, राजस्थान द्वारा 'मिशन ओबी लॉस' की शुरुआत की गई है।

-:7:-



राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विकसित 'शाला दर्पण पोर्टल'

चर्चा में क्यों?

- डिजिटल युग में शिक्षा को नई दिशा देने के उद्देश्य से राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा संचालित 'शाला दर्पण पोर्टल' विद्यार्थियों के लिए एक समग्र शैक्षणिक मंच के रूप में स्थापित हो चुका है।

डिजिटल क्रांति की दिशा में शिक्षा विभाग का नवाचार

विषयवार वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और आरबीएसई पाठ्यक्रम आधारित ई-कॉन्टेंट, विस्तृत प्रश्न बैंक, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रमों की सामग्री और ई-पत्रिकाएँ एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध

- विद्यार्थियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में अहम भूमिका निभा रहा 'शाला संवाद'
- कक्षा 1 से 12 तक के लिए विविध और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध

RajGovOfficial

--:8:--



मुख्य बिन्दु:

- इंटीग्रेटेड शाला दर्पण पोर्टल राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग की एक ऑनलाइन डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है।
- **डिज़ाइन और विकास :** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), राजस्थान द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के लिए।
- यह पोर्टल राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों, छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा कार्यालयों से जुड़ी लाइव जानकारियों को एक ही स्थान पर संकलित करता है।
- इस पोर्टल का 'स्कूल - शाला संवाद' सेक्शन विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1 से 12 तक की विविध और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है।

इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म 'टॉक टू टीचर':

- शाला दर्पण पोर्टल का 'टॉक टू टीचर' फीचर विद्यार्थियों के लिए एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहा है।
- इस सुविधा के माध्यम से विद्यार्थी सीधे शिक्षकों से जुड़ सकते हैं और पढ़ाई से संबंधित समस्याओं, शंकाओं या कठिनाइयों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

HZL का इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट : चंदेरिया (चित्तौड़गढ़)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) ने 250 हेक्टेयर क्षेत्र में पारिस्थितिक बहाली परियोजना (इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट) विकसित करने के लिए 'द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट' (TERI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

Hindustan Zinc partners TERI for 250-hectare ecological restoration project in Rajasthan



मुख्य बिन्दु:

- **प्रोजेक्ट का विकास :** चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स में।
- यह पहल हिंदुस्तान जिंक की व्यापक ESG रणनीति के अनुरूप है, जिसमें भूमि पुनर्स्थापन, जैव विविधता संरक्षण, जल प्रबंधन और कार्बन उत्सर्जन में कमी शामिल है।
- इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन या पारिस्थितिक बहाली परियोजना एक ऐसी वैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रक्रिया है, जिसके तहत मानवीय गतिविधियों, प्रदूषण या प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट, क्षतिग्रस्त या निम्नीकृत (degraded) हो चुके पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारकर उसकी मूल प्राकृतिक स्थिति में वापस लाया जाता है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) :

- हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) वेदांता समूह की एक कंपनी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादक है और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 चांदी उत्पादकों में से एक है।
- **स्थापना :** वर्ष 1966 में।
- **मुख्यालय :** उदयपुर (राजस्थान)
- इस कंपनी ने वर्ष 2024 में इकोजेन (EcoZen) लॉन्च किया, जो एशिया का पहला 'लो कार्बन ग्रीन जिंक' ब्रांड है।
- हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वर्ष 2025 में 'इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स (ICMM)' में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी है।
- हिंदुस्तान जिंक को हाल ही में S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट - 2025 में लगातार तीसरे वर्ष विश्व की सबसे टिकाऊ धातु और खनन कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है।

राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में खजूर की खेती

चर्चा में क्यों?

- ICAR - केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर द्वारा 09 जून, 2026 को जोधपुर में 'खजूर दिवस' मनाया गया।



मुख्य बिन्दु:

- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शुष्क क्षेत्रों में खजूर की खेती को बढ़ावा देना है।
- कार्यक्रम के दौरान काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त खजूर की विभिन्न उन्नत किस्मों; जैसे - हलावी, बरही, मेडजूल, खुनेजी और ADP - 1 की वैज्ञानिक खेती, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विशेषताओं का प्रदर्शन किया गया।
- **उपयुक्त जिले :** बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जालौर, श्रीगंगानगर और चूरू।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI), जोधपुर
- **स्थापना:** वर्ष 1959 में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अंतर्गत।
- **मुख्यालय :** जोधपुर।
- **क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र :** बीकानेर, जैसलमेर, पाली, जालौर और भुज (गुजरात) में।
- **मुख्य उद्देश्य :** शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों (Arid & Semi-Arid Regions) में टिकाऊ कृषि, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं ग्रामीण आजीविका सुधार हेतु अनुसंधान करना।

प्रमुख कार्यक्षेत्र :

- **भूमि एवं जल संरक्षण** - मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव रोकना और जल का समुचित उपयोग।
- **वनस्पति अनुसंधान** - कम पानी वाली फसलें, चारा उत्पादन और बागवानी पद्धतियों का विकास।
- **पशुपालन अनुसंधान** - ऊँट, भेड़, बकरी आदि शुष्क क्षेत्र के पशुओं की नस्ल सुधार व प्रबंधन।
- **प्रौद्योगिकी विकास** - मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए सिंचाई तकनीक, वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा आधारित उपकरण।
- **जलवायु अनुसंधान** - मरुस्थल में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी को वीर चक्र ■ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बारां जिले के कुंजेड़ निवासी भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी को 'ऑपरेशन सिंदूर' में असाधारण शौर्य और रणनीतिक नेतृत्व के लिए भारत के तीसरे सबसे बड़े युद्धकालीन वीरता पुरस्कार 'वीर चक्र' से सम्मानित किया। ■ युद्ध के दौरान वीरता और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले शीर्ष तीन वीरता पुरस्कार : 1. परमवीर चक्र, 2. महावीर चक्र और 3. वीर चक्र।
2.	16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता ■ आयोजन : 4 से 7 जून, 2026 तक पाली में। ■ विजेता : फाइनल में जयपुर ने अलवर को 3-1 से हराया। ■ तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में हनुमानगढ़ ने भीलवाड़ा को हराया।
3.	युवा संगम का छठा चरण ■ युवा संगम फेज - 6 के तहत हाल ही में कर्नाटक के IIIT धारवाड़ के 47 डेलीगेट्स और 6 कॉर्डिनेटर्स का दल जयपुर स्थित मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुँचा। ■ युवा संगम भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' पहल के तहत चलाया जा रहा एक प्रमुख युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम है। ■ इसका मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, पर्यटन और विकास से जोड़कर उनमें राष्ट्रीय एकता और आपसी समझ को बढ़ावा देना है।

4.	प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा ■ हाल ही में, राजस्थान पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने राज्य को पूरी तरह से नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से 'प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा' की शुरुआत की। ■ इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और छात्र-छात्राओं को नशे के जाल से बचाना है। ■ इस प्रोजेक्ट के तहत संस्थानों के प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों को 'नशा विरोधी योद्धा' बनाया जा रहा है, जो अपने-अपने संस्थानों के आसपास 500 मीटर क्षेत्र को ड्रग्स फ्री रखने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
5.	नॉर्थ जोन नेशनल स्ववैश हाई-परफॉर्मेंस कैंप : जयपुर ■ नॉर्थ जोन नेशनल स्ववैश हाई-परफॉर्मेंस कैंप का आयोजन पहली बार जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) स्टेडियम स्थित राजस्थान स्ववैश एकेडमी में किया गया। ■ आयोजन : स्ववैश फेडरेशन ऑफ इंडिया (SRFI), भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI)
6.	देवांशी शर्मा : विश्व योगासन चैंपियनशिप - 2026 में स्वर्ण पदक ■ अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप - 2026 में जयपुर निवासी देवांशी शर्मा ने सीनियर-बी हैंड बैलेंस इंडिविजुअल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
7.	MGSU एवं RKCL के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) ■ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के 23वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए विश्वविद्यालय ने अपने स्नातक (UG) पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के इंटर्नशिप हेतु राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) के 4 क्रेडिट/120 घंटे के 11 रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान की।

	■ इस संबंध में MGSU एवं RKCL के मध्य एक MoU पर हस्ताक्षर किए गए। ■ RKCL के इन सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को ऑडियो विजुअल कंटेंट, हैंड्स-ओन ट्रेनिंग एवं प्रोजेक्ट्स की सुविधा प्रदान की जायेगी, जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार प्रोग्राम चुन कर अपने कौशल एवं व्यक्तित्व का विकास कर पायेंगे।
8.	इंडिया फूड बिजनेस एक्सपो - 2026 ■ आयोजन : 5 से 7 जून, 2026 तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC), जयपुर में। ■ आयोजक : राजस्थान उद्योग व्यापार महासंघ और TPN सोल्यूशन्स। ■ उद्देश्य : खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और खाद्य उद्योग से जुड़े व्यापार को बढ़ावा देना।
9.	राजस्थान लीग सीनियर विमेंस A डिवीज़न 2025-26 ■ आयोजन स्थल : RUFC एकेडमी, जयपुर। ■ आयोजक : राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन (RFA) ■ विजेता टीम : जिंक फुटबॉल एकेडमी (ZFA), जावर (उदयपुर) ■ उपविजेता टीम : जयपुर सिटी FC
10.	'फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026' में राजस्थान के 2 युवा शामिल ■ प्रतिष्ठित 'फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026' की सूची में जयपुर के दो युवा उद्यमियों 'धवल जैन और जय शर्मा' को शामिल किया गया है। ■ धवल जैन और जय शर्मा ने बिहार के अमन कुमार के साथ मिलकर वर्ष 2023 में हेल्थटेक स्टार्टअप "मेव हेल्थ" की स्थापना की।



फूड प्लैनेट पुरस्कार 2026

[THE HINDU]



चर्चा में क्यों?

- आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक कृषि (एपीसीएनएफ) कार्यक्रम ने फूड प्लैनेट पुरस्कार 2026 जीता है।
- फूड प्लैनेट पुरस्कार की स्थापना 2019 में स्वीडन के कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन द्वारा की गई थी।
- इसे वैश्विक खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन लाने के लिए समर्पित विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है।
- एपीसीएनएफ का चयन इस बात का प्रतीक है कि किसी भारतीय पहल को पहली बार यह पुरस्कार मिला है।



मुख्य बिन्दु:

एपीसीएनएफ कार्यक्रम

- रायथु साधिकर संस्था (आरवाईएसएस) के माध्यम से 2016 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करके प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देता है।

नॉर्वे शतरंज, 2026

[स्रोत: AIR, FIDE और The Hindu]

चर्चा में क्यों?

- नॉर्वे शतरंज, 2026 टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रग्नानंद रमेशबाबू ने 10वें और अंतिम दौर में जर्मन खिलाड़ी विंसेंट कीमर को हराकर नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीता तथा इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए।



मुख्य बिन्दु:

- **आयोजन:** 25 मई, 2026 से 5 जून, 2026 तक डिचमैन ब्योर्विका लाइब्रेरी, ओस्लो, नॉर्वे में आयोजित की गई।
- **रैंकिंग:**
 - **नॉर्वे पुरुष शतरंज, 2026:**

रैंक	विजेता	देश	अंक
1.	प्रग्नानंदा रमेशबाबू	भारत	18
2.	वेस्ली सो	USA	17
3.	अलीरेज़ा फ़िरोज़जा	फ़्रांस	15½
4.	मैग्नस कार्लसन	नॉर्वे	13
5.	विंसेंट कीमर	जर्मनी	11
6.	गुकेश डोम्माराजू	भारत	8

Daily Current Affairs

Date : 09 June, 2026



• नॉर्वे महिला शतरंज, 2026:

रैंक	विजेता	देश	अंक
1.	बिबिसारा असौबायेवा	कजाकिस्तान	16.5
2.	झू जिनर	चीन	16
3.	अन्ना मुज़िचुक	यूक्रेन	15

- प्रग्नानंद ने क्लासिकल गेम्स में मैग्नस कार्लसन को दो बार हराया और मौजूदा विश्व चैंपियन डी. गुकेश को भी हराया।
- इस टूर्नामेंट में दिव्या देशमुख 10 अंक और हम्पी कोनेरू 9 अंक के साथ क्रमशः 5 वें और 6 वें स्थान पर रही।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

-:19:-



UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

मुक्केबाज जैस्मीन लैंबोरिया

[स्रोत: AIR]

चर्चा में क्यों?

- विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लैंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है।
- एशियाई चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता प्रिया घंघास (60 किग्रा) और विश्वनाथ सुरेश (50 किग्रा) अपने-अपने वर्ग में शीर्ष तीन में शामिल हैं।
- लिवरपूल में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय मुक्केबाज़ जैस्मीन लंबोरिया ने पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता जूलिया जेरेमेटा को हराकर फेदरवेट (57 किग्रा) का खिताब हासिल किया था।



-:20:-

एस भरत

[स्रोत: AIR]



चर्चा में क्यों?

- विकेटकीपर और बल्लेबाज के एस भरत ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है।
- उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- भरत, जून, 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने वाली भारतीय टीम में शामिल थे।





आर्थिक घटनाक्रम



व्यापार करने में सुगमता: भारत के व्यापार ढांचे को सुदृढ़ बनाना

[PIB]



चर्चा में क्यों?

- भारत ने एक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-संचालित और विश्वास-आधारित व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए व्यापक सुधार किए हैं, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई है।



मुख्य बिन्दु:

भारत में व्यापार करने में आसानी के क्षेत्र में हुई प्रगति

- विश्व बैंक की ड्रूंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 2014 में 142वें स्थान से सुधरकर 2019 में 63वें स्थान पर आ गई, जो नियामक वातावरण में महत्वपूर्ण सुधारों को दर्शाता है।
- आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत की स्थिति 2021 में 43वें स्थान से सुधरकर 2025 में 41वें स्थान पर पहुंच गई है।
- भारत को विश्व बैंक के गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी इंडेक्स के ग्रुप ए में लगातार स्थान दिया गया है, जो उन्नत डिजिटल गवर्नेंस क्षमताओं को दर्शाता है।
- संयुक्त राष्ट्र के ई-गवर्नमेंट सर्वेक्षण ने ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओं, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी-आधारित शासन में भारत की प्रगति को मान्यता दी है।

व्यवसाय में प्रवेश और औपचारिकीकरण में सुधार

- **स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास:** स्टार्टअप इंडिया पहल ने वित्तीय सहायता, इनक्यूबेशन सुविधाओं और नियामक प्रोत्साहनों के माध्यम से नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया है।

मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2016 में 502 से बढ़कर मार्च 2026 तक 2.23 लाख से अधिक हो गई।

- **कंपनी पंजीकरण का सरलीकरण:** SPICe + प्लेटफॉर्म ने पैन, टैन, जीएसटी, ईपीएफओ, ईएसआईसी और बैंक खाता खोलने जैसे कई पंजीकरणों को एक ही ऑनलाइन आवेदन में एकीकृत कर दिया है।

- **MSME का औपचारिकीकरण:** उद्यम पंजीकरण पोर्टल ने MSME के कागज रहित और स्व-घोषणा आधारित पंजीकरण को सक्षम बनाया है।

भूमि एवं संपत्ति प्रशासन में सुधार

- डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम ने भूमि अभिलेखों और भूमि अभिलेखीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया है, जिससे विवाद कम हुए हैं और पारदर्शिता में सुधार हुआ है।

यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूएलपीआईएन) ने भूमि पार्सल के लिए एक अद्वितीय डिजिटल पहचान बनाई है, जिससे सटीक भूमि प्रबंधन संभव हो पाता है।

- राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली ने संपत्ति लेनदेन को सुव्यवस्थित किया है और संपत्ति और दस्तावेज़ पंजीकरण के लिए एक संपूर्ण उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस प्रदान करके ईओडीबी को बढ़ावा दिया है।



नियामक अनुमोदनों को सरल बनाना

- **श्रम सुधार:** श्रम संहिता ने अनेक श्रम कानूनों को सरल कानूनी ढाँचे में समेकित कर दिया है।
एकल पंजीकरण, एकल रिटर्न और अखिल भारतीय लाइसेंस ने व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत को कम कर दिया है।
- राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली कई मंत्रालयों और राज्यों से अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करती है।
- **पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियां:** परिवेश पोर्टल ने पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनियमन संबंधी स्वीकृतियों को डिजिटाइज़ कर दिया है।

बाजार पहुंच और रसद में सुधार

- सरकारी ई-मार्केटप्लेस ने एक पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए खरीद के अवसरों का विस्तार किया है। इसने सार्वजनिक खरीद में समावेशी भागीदारी को बढ़ावा दिया है।
- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) ने एक खुला और अंतरसंचालनीय डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम बनाया है जो छोटे व्यवसायों को बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाता है।
- पीएम गतिशक्ति ने एकीकृत अवसंरचना नियोजन के माध्यम से बहुआयामी कनेक्टिविटी में सुधार किया है।

--:24:--

ऋण तक पहुंच सुगम

- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:** पीएम मुद्रा योजना ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन का विस्तार किया है।
- क्रेडिट असेसमेंट मॉडल स्वचालित ऋण मूल्यांकन के लिए डिजिटल वित्तीय डेटा का उपयोग करता है, जिससे प्रसंस्करण समय कम होता है और ऋण वितरण में सुधार होता है।
- ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम ने कॉर्पोरेट खरीदारों और सरकारी संस्थाओं से भुगतान की तेजी से प्राप्ति को सक्षम बनाकर एमएसएमई के लिए तरलता में सुधार किया है।

कर सुधार और अनुपालन सरलीकरण

- **वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी):** इसने अनेक अप्रत्यक्ष करों को एक एकीकृत कर संरचना से प्रतिस्थापित कर दिया है, जिससे एक साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हुआ है। इससे करों के असमान वितरण में कमी आई है, पारदर्शिता में सुधार हुआ है और अंतरराज्यीय व्यापार को सुगम बनाया गया है।
- ई-वे बिल प्रणाली ने कई परमिटों को एक ही इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ से बदलकर राज्यों के बीच माल की आवाजाही को सुव्यवस्थित कर दिया है।

सीमा पार व्यापार को बढ़ावा

- डिस्ट्रिक्ट्स एज़ एक्सपोर्ट हब्स पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर निर्यात, विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा देना है।
- ICEGATE (इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे) भारतीय सीमा शुल्क और व्यापारिक समुदाय के बीच सभी इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान के लिए एक केंद्रीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है।

यह ई-फाइलिंग, ऑनलाइन संशोधन जमा करने, ऑनलाइन शुल्क भुगतान और प्रश्नों के समाधान सहित कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है।

- ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म सभी निर्यातकों, जिनमें लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भी शामिल हैं, को व्यापक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी जानकारी और सेवाएं प्रदान करता है, जिससे उन्हें वैश्विक बाजारों तक आसान पहुंच मिलती है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विस्तार

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने त्वरित, सुरक्षित और कम लागत वाले लेनदेन को सक्षम बनाकर डिजिटल भुगतान में क्रांति ला दी है।
- एंटीटीलॉकर, संस्थाओं के लिए एक डिजिटल लॉकर है जो संगठनों को डिजिटल दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को संगृहीत करने, साझा करने और सत्यापित करने के लिए एक सुरक्षित, क्लाउड-आधारित मंच प्रदान करके सशक्त बनाता है।

विश्वास-आधारित शासन ढांचा तैयार करना

- जन विश्वास सुधारों के तहत व्यापार से संबंधित सैकड़ों छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इन सुधारों से प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए आपराधिक अभियोजन का डर कम हुआ है और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिला है।
- दिवालियापन एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 ने दिवालियापन समाधान के लिए एक समयबद्ध ढांचा स्थापित किया।

बाद में किए गए संशोधनों से प्रक्रियात्मक दक्षता में सुधार हुआ है, लेनदारों के अधिकारों को मजबूती मिली है और निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।

Daily Current Affairs

 Date : 09 June, 2026



चुनौतियाँ

- विवादों, प्रक्रियात्मक जटिलताओं और न्यायिक लंबित मामलों के कारण भूमि अधिग्रहण और अनुबंध प्रवर्तन में लगातार देरी हो रही है।
- विभिन्न राज्यों और जिलों में सुधारों के कार्यान्वयन में भिन्नता पाई जाती है, जिससे एक असमान व्यावसायिक वातावरण उत्पन्न होता है।
- अन्य प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक्स की लागत अपेक्षाकृत अधिक बनी हुई है, जिससे औद्योगिक प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है।
- लघु एवं मध्यम उद्यम, वित्त, प्रौद्योगिकी, कुशल जनशक्ति और वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने में लगातार बाधाओं का सामना कर रहे हैं।
- दिवालियापन और नियामक ढांचे में सुधार के बावजूद, वाणिज्यिक विवादों का समाधान करना अभी भी समय लेने वाला है।
- वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएँ और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान निवेश और व्यापार वृद्धि के लिए जोखिम पैदा करते रहते हैं।

-:27:-



भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

रक्षा अलंकरण समारोह, 2025 (चरण-I)

[स्रोत: PIB]

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रपति ने 8 जून, 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह, 2026 के प्रथम चरण के दौरान रक्षा बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को 7 कीर्ति चक्र (जिनमें 2 मरणोपरांत शामिल हैं), 15 वीर चक्र (जिनमें 3 मरणोपरांत शामिल हैं) और 29 शौर्य चक्र (जिनमें 1 मरणोपरांत शामिल है) प्रदान किए।





मुख्य बिन्दु:

- **शौर्य चक्र:** कर्नल नीतेश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, मेजर आशीष कुमार, कांस्टेबल/जीडी संजय तिवारी और कांस्टेबल/जीडी फेदा हुसैन दार, मोहम्मद शफीक, कमांडर सूरज पराशर, राम गोयल, सद्दाम हुसैन, विपिन विल्सन, भोज राम साहू, अभिमन्यु सिंह, भार्गव कलिता, लीशंगथेम दीपक सिंह, अंशुल बाल्टू, शिवकांत यादव, सूबेदार पीएच मोसेस, मेजर विवेक, मंगलेम संग वेईफेई, घाटगे आदित्य श्रीकुमार, योगेंद्र सिंह ठाकुर, शमशेर सिंह, राहुल सिंह, धुरबा ज्योति दत्ता, दिलना के और कमांडर रूपा ए।
- **वीर चक्र:** कोशांक लांबा, रणजीत सिंह सिद्धू, मनीष अरोड़ा, अनिमेष पटनी, कुणाल कालरा, जॉय चंद्र, सुशील बिष्ट, सार्थक कुमार, सिद्धांत सिंह, रिजवान मलिक, आरश्वीर सिंह ठाकुर और सतीश कुमार।
- **कीर्ति चक्र:** मीनाक्षी सुंदरम ए, सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, अर्शदीप सिंह, प्रशांत बालकृष्णन और लालरीनावमा सैलो।
- **शौर्य चक्र (मरणोपरांत):** बलदेव चंद
- **वीर चक्र (मरणोपरांत):** मोहम्मद इम्तेयाज, दीपक चिंगखम और राइफलमैन सुनील कुमार।
- **कीर्ति चक्र (मरणोपरांत):** जंजाल प्रवीण प्रभाकर और शशांक तिवारी

योजनाएँ एवं नीतियाँ

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान: 10 वर्ष पूर्ण

[स्रोत: PIB]

चर्चा में क्यों?

- 9 जून, 2026 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा PMSMA के दस वर्ष एक दशक की देखभाल समारोह राष्ट्रव्यापी स्तर पर आयोजन किया गया।
- स्मारक सिक्का और डाक टिकट:** प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत देश भर में सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में इस योजना के एक दशक की सेवा को प्रदर्शित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा 75 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का और एक 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट जारी किया।



The infographic features a pregnant woman on the left and a portrait of Prime Minister Narendra Modi on the right. The central text reads '10 दशक सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने का एक दशक।' (10 Decade of promoting safe motherhood). Below this, it states 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) - सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक प्रसवपूर्व जांच के 10 वर्ष।' (Prime Minister's Safe Motherhood Mission (PMSMA) - 10 years of comprehensive pre-natal checkups in government health facilities). A banner at the bottom says 'आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध निःशुल्क सेवाएं' (Free services available at your nearest health center). The services listed are: विशेषज्ञ द्वारा सेवाएं (Services by specialists), अल्ट्रासाउंड (Ultrasound), उच्च जोखिम गर्भावस्था (HRP) की पहचान एवं प्रबंधन (Identification and management of High Risk Pregnancy), सुरक्षित प्रसव तक उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की व्यक्तिगत निगरानी व जांच (Personalized monitoring and checkups for high-risk pregnant women until safe delivery), PMSMA सत्र में भाग लेने के लिए गर्भवती महिलाओं को परिवहन हेतु प्रोत्साहन (Incentives for pregnant women to participate in PMSMA sessions for transport), सुरक्षित प्रसव के लिए निकटतम प्रथम रेफरल इकाई (FRU) से संपर्क (Contact the nearest primary referral unit for safe delivery), रक्त व मूत्र की सभी आवश्यक जांच (All necessary blood and urine tests), आयर्न, कैल्शियम गोली एवं टीड टीकाकरण (Iron, Calcium tablets and Tetanus vaccination), and पोषण, संतुलित आहार एवं परिवार नियोजन पर परामर्श (Nutrition, balanced diet and family planning advice). At the bottom, it says 'हर महीने की 9 तारीख को नियमित जांच के लिए अपने नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं।' (Visit your nearest government health center for regular checkups on the 9th of every month). There are also buttons for '#9कासंकल्प' and '#PMSMAके10साल'.

--:30:--

मुख्य बिन्दु:

■ अभियान की आवश्यकता:

- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के शुभारंभ से पहले 2014-16 के दौरान, भारत में मातृ मृत्यु दर (MMR) प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 थी।
- भारत ने वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु दर को प्रति एक लाख जन्मों पर 70 से कम करने के सतत विकास लक्ष्य (SDG) को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता।

■ शुरुआत: 9 जून, 2016 को शुरू की गई।

■ उद्देश्य: सभी गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को, विशेष रूप से गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) सेवाएं निःशुल्क प्रदान करना।

■ मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

■ मुख्य लक्ष्य: इसका मुख्य लक्ष्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का शीघ्र पता लगाकर और उनका त्वरित प्रबंधन करके मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है।

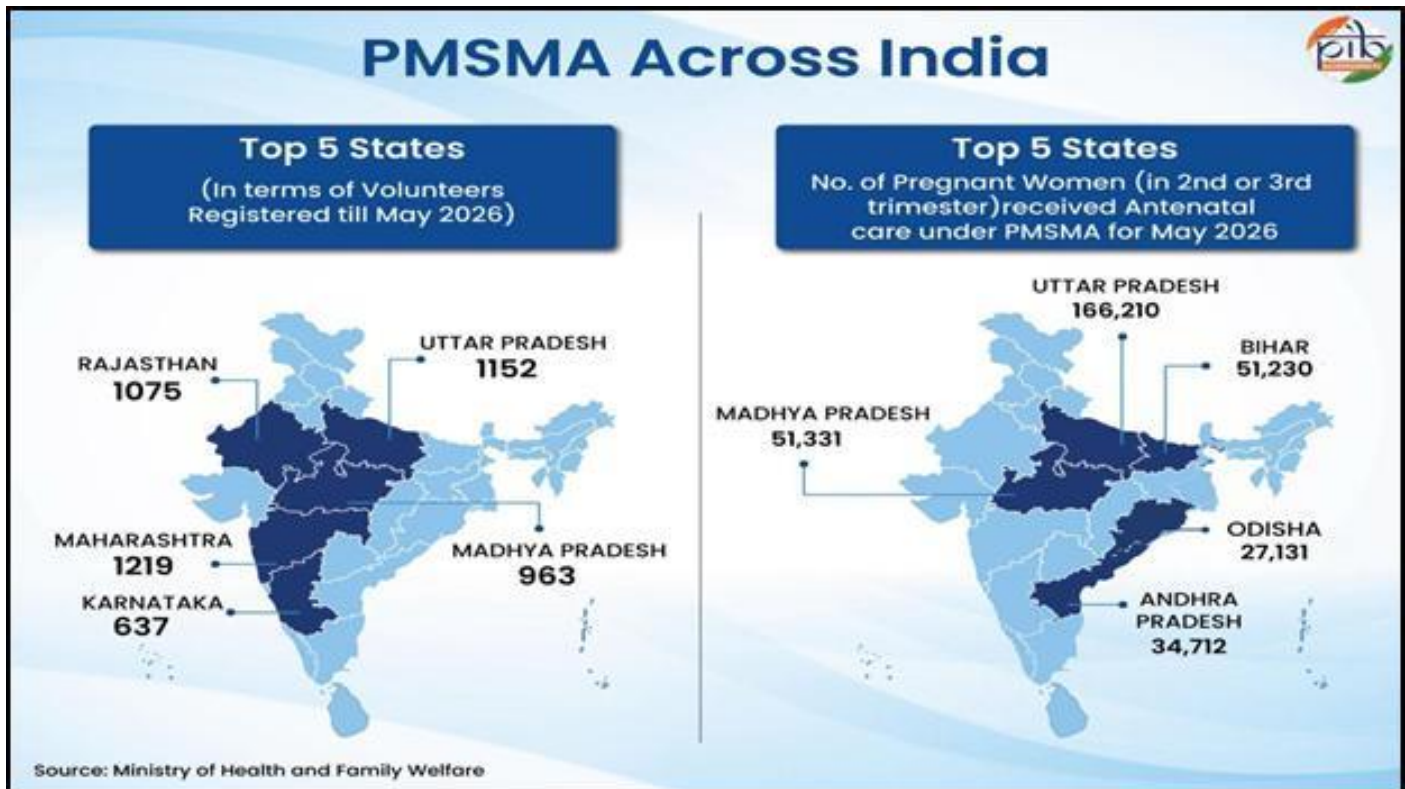
■ प्रमुख विशेषताएं:

KEY FEATURES OF PMSMA

- Monthly antenatal checkups on the 9th of every month at public health facilities.
- Services provided by OBGY specialists, radiologists, physicians, with private sector support.
- Minimum package for every woman: essential investigations (including 2nd trimester ultrasound) and medicines (IFA, calcium).
- Single window system for all ANC services and investigations.
- Special focus on:
 - Unregistered or missed ANC women
 - Dropouts
 - High-risk pregnancies
- Distribution of Mother and Child Protection Cards and safe motherhood booklets.
- High-risk pregnancy identification:
 - Green sticker: no risk
 - Red sticker: high risk

- विस्तारित PMSMA (E- PMSMA):** E- PMSMA रणनीति जनवरी, 2022 में शुरू की गई थी ताकि 25 उच्च जोखिम वाली गर्भवती (HRP) महिलाओं की सुरक्षित प्रसव तक ट्रेसिंग और ट्रेकिंग सुनिश्चित की जा सके।
 - E- PMSMA की प्रमुख विशेषताएं: मानव संसाधन विकास संगठनों (HRP) की नाम-आधारित पंक्ति सूची, अतिरिक्त PMSMA सत्र का प्रावधान (महीने में अधिकतम 4 बार) और स्वस्थ परिणाम प्राप्त होने तक (प्रसव के 45वें दिन तक) एचआरपी की व्यक्तिगत निगरानी।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों के साथ एकीकरण:** जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN), पोषण अभियान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के साथ एकीकरण किया गया।
- सेवाएं:** प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ द्वारा कम से कम एक व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच या व्यापक आपातकालीन प्रसूति एवं नवजात शिशु देखभाल सुविधा।
- आपातकालीन सेवाएं:** दूसरी या तीसरी तिमाही के दौरान व्यापक आपातकालीन प्रसूति एवं नवजात शिशु देखभाल/ बुनियादी आपातकालीन प्रसूति एवं नवजात शिशु देखभाल में प्रशिक्षित डॉक्टर।
- सेवा पैकेज में आवश्यक रक्त और मूत्र जांच और अल्ट्रासोनोग्राफी शामिल हैं।
- प्रत्येक गर्भवती महिला को पोषण, उचित प्रसव योजना और जटिलताओं से निपटने की तैयारी के बारे में परामर्श प्रदान करना।
- **उपलब्धियाँ:**
 - प्रसवपूर्व सेवाएँ:** 9 जून, 2026 को एक दशक पूरा होने पर, PMSMA के तहत 75 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को नियमित प्रसवपूर्व जांच सेवाओं के अतिरिक्त प्रसवपूर्व सेवाएं प्राप्त हो चुकी हैं।
 - 1.8 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आयुष्मान आरोग्य शिविर:** देश के 1.8 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
 - मातृ मृत्यु दर:** भारत ने मातृ मृत्यु दर में 43 अंकों की कमी हासिल की है, जिससे यह 2014-16 और 2022-24 के बीच प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर 87 मातृ मृत्यु हो गई है।

4. रैंकिंग:



अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

- **मातृ मृत्यु दर (MMR):** इसे किसी निश्चित अवधि में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। मातृ मृत्यु से तात्पर्य गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था समाप्त होने के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित या उससे बिगड़ने वाले कारणों से होने वाली महिला की मृत्यु से है, जिसमें आकस्मिक या संयोगवश होने वाली मृत्यु शामिल नहीं है।

भव्य योजना एवं पोर्टल

[स्रोत: PIB]

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के संचालन हेतु भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया।



मुख्य बिन्दु:

भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्या):

- **परिचय:** भव्य (BHAVYA) एक केंद्र द्वारा अनुमोदित औद्योगिक अवसंरचना योजना है जिसका उद्देश्य 100 विश्व स्तरीय प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास करना है जिनमें उपयोग के लिए तैयार सुविधाएं होंगी, जिससे उद्योगों को प्रक्रियात्मक देरी के बिना जल्दी से परिचालन शुरू करने में मदद मिलेगी।

-:34:-

Daily Current Affairs

Date : 09 June, 2026



- **शुरुआत:** मार्च, 2026
- **परिव्यय:** 33,660 करोड़ रुपये
- **नोडल मंत्रालय:** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य राज्यों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में शहरों में और उसके आसपास 100 निवेश-तैयार प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क (100-1000 एकड़) विकसित करना है।
- **अवधि:** 6 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2031-32 तक)।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (NICDC)
- **पात्रता:** 100 एकड़ (पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 25 एकड़) से लेकर 1000 एकड़ तक के औद्योगिक पार्कों का चयन किया जाएगा।
- **उद्देश्य:**
 - विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास को गति देने के लिए।
 - पूर्व-अनुमोदित बुनियादी ढांचे के माध्यम से व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना।
 - क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना।
 - बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए।
- **कार्यान्वयन तंत्र:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अंतर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) द्वारा राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है।

--:35:--



Daily Current Affairs

 Date : 09 June, 2026



- **वित्तीय सहायता:** पात्र परियोजनाओं के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपये तक की सहायता उपलब्ध होगी, जबकि निजी विकासकर्ताओं के साथ साझेदारी में विकसित पार्कों को प्रति एकड़ 50 लाख रुपये तक या बुनियादी ढांचे की लागत का 50%, जो भी कम हो, तक की सहायता प्राप्त होगी।
- **साझेदारी:** भारत सरकार, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम के माध्यम से बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग करेगी, जो 51:49 मॉडल के अंतर्गत राज्यों के साथ साझेदारी करेगा।
- **लाभार्थी:**
 - **प्राथमिक ग्राहक:** विनिर्माण इकाइयाँ, लघु एवं मध्यम उद्यम, स्टार्टअप और वैश्विक निवेशक जो तैयार औद्योगिक अवसंरचना की तलाश में हैं।
 - **द्वितीयक वर्ग:** श्रमिक, लॉजिस्टिक्स प्रदाता, सेवा क्षेत्र के उद्यम और स्थानीय समुदाय।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
 1. **बड़े पैमाने पर औद्योगिक पार्क:** सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 से 1000 एकड़ के पार्कों का विकास
 2. **प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर:** पूर्व-अनुमोदित भूमि, उपयोगिताएँ और स्वीकृतियाँ उद्योगों को योजना से उत्पादन की ओर तेजी से बढ़ने में सक्षम बनाती हैं।
 3. **वित्तीय सहायता:**
 - मूलभूत, मूल्यवर्धित और सामाजिक अवसंरचना के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपये तक का अनुदान।
 - बाह्य कनेक्टिविटी अवसंरचना के लिए 25% तक समर्थन

-:36:-



4. एकीकृत अवसंरचना पारिस्थितिकी तंत्र:

- मुख्य क्षेत्र: सड़कें, जल निकासी, भूमिगत उपयोगिताएँ, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियाँ
- मूल्यवर्धन: कारखाना परिसर, परीक्षण प्रयोगशालाएँ, गोदाम
- सामाजिक: कामगारों के लिए आवास और सुविधाएं

5. व्यापार करने में सुगमता लाने वाले सुधार:

- सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम
- राज्य के नेतृत्व में निवेशक-अनुकूल सुधार

6. चुनौती-आधारित परियोजना चयन: यह सुनिश्चित करता है कि केवल निवेश के लिए तैयार और सुधार-उन्मुख प्रस्तावों को ही मंजूरी दी जाए।

7. पीएम गतिशक्ति के साथ संरेखण: बहुआयामी कनेक्टिविटी और कुशल लॉजिस्टिक्स एकीकरण को सक्षम बनाता है।

8. सतत् औद्योगिक विकास:

- हरित ऊर्जा एकीकरण
- भूमिगत उपयोगिता गलियारे (बिना खुदाई वाला मॉडल)



अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



नेपाल के 'नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस (NPI)' के साथ UPI को जोड़ा गया

[AIR]



चर्चा में क्यों?

- भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस (NPI) के बीच लिंक की शुरुआत की गई ताकि दोनों देशों के बीच धन प्रेषण को सहज बनाया जा सके।



मुख्य बिन्दु:

UPI

- **शुरुआत:** 11 अप्रैल, 2016 को 'भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम' (NPCI) द्वारा।
- **विकास:** UPI एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। इसका विकास NPCI ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के विनियामक पर्यवेक्षण में किया है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** भारत के कुल डिजिटल भुगतान में UPI की हिस्सेदारी लगभग 85% है और विश्व स्तर पर रियल-टाइम भुगतान में इसकी हिस्सेदारी 49% है। इस तरह यह प्रणाली वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है।

केशम द्वीप

[ECONOMIC TIMES]

चर्चा में क्यों?

- अमेरिका ने केशम द्वीप पर निगरानी सुविधाओं पर हमला किया।

केशम द्वीप:

- **अवस्थिति:** ईरानी मुख्य भूमि के दक्षिणी तट (होर्मोज़गान) के साथ जाग्रोस पर्वतमाला के दक्षिणी किनारे पर।
- यह होर्मुज जलसंधि के निकट फारस की खाड़ी में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है।
- इसे "सात अजूबों का द्वीप" भी कहा जाता है।

भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक

[विदेश मंत्रालय]



चर्चा में क्यों?

- विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री के साथ भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह-अध्यक्षता की।
- दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।



-:40:-

भारत के लिए इंडोनेशिया का महत्त्व

- **नीतिगत सामंजस्य:** भारत की "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" और "इंडो-पैसिफिक ओशनस् इनिशिएटिव" इंडोनेशिया के "ग्लोबल मैरीटाइम फुलक्रम" विजन के साथ अच्छी तरह से मेल खाती हैं, जिससे समुद्री सुरक्षा, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग के लिए तालमेल बनता है।
- **प्रभाव का प्रतिसंतुलन:** इंडोनेशिया की रणनीतिक स्थिति और बढ़ता प्रभाव हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व का प्रतिसंतुलन करने में मदद कर सकता है, जो भारत के रणनीतिक हितों के अनुरूप है।
- **समुद्री सुरक्षा:** हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित इंडोनेशिया की रणनीतिक स्थिति इसे क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाती है।
- **आतंकवाद विरोधी प्रयास:** उग्रवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध से उत्पन्न साझा चुनौतियों को देखते हुए, आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सहयोग आवश्यक है।
- **गहरी जड़ें जमाएँ सांस्कृतिक संबंध:** ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध, विशेष रूप से हिंदू परंपराओं और रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का प्रभाव, दोनों देशों के बीच मजबूत जन-संबंधों को बढ़ावा देता है।
- **पर्यटन क्षमता:** इन साझा सांस्कृतिक जड़ों का लाभ उठाकर दोनों देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जा सकता है।